



एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2023)

www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

कृषि में स्टार्टअप - एक वैकल्पिक रोजगार का साधन

(सूरज कुमार एवं यशवंत कुमार पटेल)

खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ.ग.

संवादी लेखक का ईमेल पता: skbhardwaj2104@gmail.com

स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 16 जनवरी 2016 को भारत में, बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। इस योजना में उद्योगों के लिए फंडिंग सहायता, मार्गदर्शन तथा उद्योग भागीदारी के अवसर सुनिश्चित करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान किया जाता है।

कृषि में स्टार्टअप शुरू करने शासन की कुछ प्रमुख योजनायें

1. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम: सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अन्तर्गत देश के हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा कृषि-आधारित उद्योग-धंधों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और किसानों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है। इसके अलावा, क्षेत्रीय-स्तर पर ही ग्रामीणों की समस्याओं और चुनौतियों का निदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत बदलावों के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है।

2. एग्रीबिजनेस: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नाबार्ड के सहयोग से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए एग्रीबिजनेस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों द्वारा फसल उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी व प्राप्त फसल उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना है। इसके अन्तर्गत, ग्रामीण युवाओं को कृषि तकनीकी और मैनेजमेंट तकनीकी के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ स्वयं का एग्रीबिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है। इसके तहत, कृषि स्नातकों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सम्बन्धी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने कृषि उद्यम स्थापना के लिए विशेष स्टार्टअप ऋण सहायता योजना आरम्भ की है। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण और स्थानीय-स्तर पर लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: इसके अन्तर्गत, सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है। इसके बाद सम्बन्धित उद्योग में उन्हें रोजगार दिलाने में भी सहायता करती है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत आज देशभर में ग्यारह सौ से ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं जो लगभग 300 व्यवसायों में आधुनिक कौशल प्रदान करते हैं।

4.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: इसके अन्तर्गत गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है और उन्हें किसी एक कार्य में कौशल प्रदान किया जाता है जिसमें आमदनी की पर्याप्त सम्भावना हो। कुशलता प्राप्त करने के बाद उनके लिए किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की अद्भुत मिसाल है।

5.एस्पायर: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में इनोवेशन, ऑन्प्रन्योरशिप (स्वरोजगार) और कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी जिसे हाल में नए प्रावधानों के साथ अधिक उपयोगी बनाया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के दौरान 80 आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर्स और 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 75,000 आकांक्षी उद्योगों को कृषि-आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, पशु आहार, दूध के संग्रहण और विपणन जैसे कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

कृषि में स्टार्टअप किन-किन चीजों में कर सकते हैं

ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों से प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्करण व परिरक्षण से अनेक कृषि-आधारित उद्योगों का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है जैसे:-

- मूंगफली से भुने हुए नमकीन दाने बनाना
- सोयाबीन से दूध व दही बनाना
- फलों से शर्बत, जैली व स्क्रॉश बनाना
- आलू व केले से शीरे व अंगूर से शराब व अल्कोहल बनाना
- विभिन्न तिलहनों से तेल निकालना
- धान से चावल
- दूध के परिरक्षण व पैकिंग के साथ-साथ इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे दूध का पाउडर, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर इत्यादि बनाना
- फूलों से सुगंधित इत्र बनाना
- लाख से चूड़ियां तथा खिलौने बनाना
- कपास के बीजों से रूई अलग करना तथा दबाव डालकर रूई का गठुर बनाना
- अचार एवं पापड़ बनाना
- ताड़, बांस, अरहर तथा कुछ अन्य फसलों एवं घासों के तनों एवं पत्तियों द्वारा डलियां, टोकरियां, चटाईयां, टोप व टोपियां तथा हस्तचालित पंखे बुनना, मूंज या सरपत से बान (चारपाई हेतु रस्सी) व मोठे बनाना, बेंत से कुर्सी व मेज बनाना
- रूई से रजाई-गद्दे व तकिए बनाने के अलावा सूत बनाकर हथकरघा-निर्मित सूती कपड़ा बनाना
- जूट एवं पटसन के रेशे से विभिन्न प्रकार के थैले टाट, निवाड़ व गलीचों की बुनाई करना
- लकड़ी का फर्नीचर बनाना, स्ट्रा बोर्ड, कार्डबोर्ड व साफ्टबोर्ड बनाना
- कृषि केंद्रों द्वारा खरपतवारनाशक, कीट नाशी तथा खाद आदि का मार्केटिंग करके इन सभी के आलावा कृषि उत्पादों का शीत भंडारण कर रोजगार के अवसर प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि-आधारित उद्योगों को अपनाते समय निम्नलिखित मुख्य बातों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए

1.ऋण व्यवस्था: रोजगार सृजन में कृषि-आधारित उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों द्वारा ग्रामीण युवकों को कम पूंजी से भी रोजगार मिल सकता है। कृषि-

आधारित उद्योग-धंधों हेतु संसाधन जुटाने के लिए पूंजी व्यवस्था करने में ग्रामीण बैंकों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कृषि विकास शाखाओं एवं सहकारी समितियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन संस्थानों के माध्यम से कृषि-आधारित उद्योग धन्धों को आरम्भ करने हेतु सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण बेरोजगारों को कम ब्याज दर तथा आसान किश्तों पर ऋण दिया जाता है।

2. कृषि-आधारित उद्योगों का चुनाव: सामान्यतः किसी उद्योग का चुनाव करने से पूर्व हम यह सोचते हैं कि इस उद्योग को करने से हमें कितना लाभ मिलेगा और लाभ मिलने की स्थिति में ही हम उस उद्योग को आगे बढ़ाते हैं। कृषि-आधारित उद्योग प्रारम्भ करते समय भी यही व्यावसायिक दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय लेते समय व्यावसायिक पहलुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम अपने संसाधनों के अनुरूप कृषि से सम्बन्धित उद्योग का चुनाव करें ताकि उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी व वैकल्पिक उपयोग करके कम लागत से प्रति इकाई अधिक लाभ कमा सकें। इसके अलावा, सम्बन्धित उद्योगों से प्राप्त उत्पादों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय बाजार में इनकी मांग को सुनिश्चित करके ही इन उद्योगों की शुरुआत करनी चाहिए।

3. जमीन व पूंजी की उपलब्धता के अनुसार ही कृषि-आधारित उद्योग लगाएं: कृषि-आधारित उद्योगों के लिए अन्य संसाधनों के साथ-साथ जमीन एवं पूंजी महत्वपूर्ण घटक हैं। अतः जिनके पास पर्याप्त जमीन एवं पूंजी है, उनके लिए तो कृषि-आधारित उद्योग लगाने हेतु कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। मगर जिनके पास जमीन तथा पूंजी कम है या नहीं है, वह भी कृषि-आधारित उद्योग हेतु जमीन को पट्टे पर ले सकते हैं।

4. लाभ लागत अनुपात का रखे ध्यान: दूसरे उद्योगों की भांति कृषि-आधारित उद्योग में लगाई गई लागत के द्वारा सम्भावित उत्पादन पर ध्यान देना ही कृषि का असली औद्योगिकीकरण है। कृषि-आधारित उद्योगों के चुनाव के समय पूंजी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कम लागत पर अधिक लाभ देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृषि-आधारित उद्योगों में लगने वाली लागत और आमदनी का ब्यौरा अवश्य रखें ताकि सही लाभ का पता चल सके और प्राप्त लाभ के आधार पर सम्बन्धित उद्योग के विस्तार पर विचार किया जा सके।

5. तकनीकी प्रशिक्षण: आज-कल कई सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाएं व बैंक किसानों, युवाओं व ग्रामीणों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि कृषि-आधारित उद्योगों को छोटे-छोटे समूह बनाकर प्रारम्भ किया जाए तो निश्चित ही अधिक लाभदायक रहेगा। इसके अलावा, आजकल हर जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा ज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिक समय-समय पर कृषि आधारित उद्योगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई ऐसे कृषि-आधारित उद्योग हैं, जिनमें थोड़ी-सी मेहनत एवं प्रशिक्षण प्राप्त करके ग्रामीण व शहरी स्तर पर स्वरोजगार आरम्भ किया जा सकता है। व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी उद्योग को शुरू करने से पहले उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी हासिल कर लें। इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण की भी अत्यंत आवश्यकता है। उपरोक्त योजनाओं व जानकारी के आधार पर कोई भी बेरोजगार यह निर्णय कर सकता है कि कृषि-आधारित उद्योगों में से अपनी परिस्थिति के अनुसार वह कौन से उद्योग को अपनाकर अपनी आजीविका चलाने के साथ-साथ लाभ भी कमा सकता है।